बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 304

वृद्धि को महत्त्व

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णयों की जानकारी दी जो औसत आवास ऋण लेने वाले आम आदमी से लेकर सरकार तक सबको प्रसन्न करने वाले हैं। एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से यह निर्णय लिया कि रीपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि यह कटौती आरबीआई के अब तक के नीतिगत रुख से अलग है। वह अब तक पूरे आकलन के बाद सख्ती की नीति अपना रहा था लेकिन अब उसने इसे निरपेक्ष कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आगामी 4 अप्रैल को एक बार फिर दरों में कटौती की जा सकती है। आम चुनावों को देखते हुए वह कटौती काफी अहम साबित हो सकती है। आरबीआई के रुख में बदलाव और कटौती का यह निर्णय वर्ष के आने वाले वक्त के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन के बाद आया है।

सालाना आधार पर आकलित की जाने वाली खुदरा महंगाई अक्टूबर 2018 के 3.4 फीसदी से कम होकर दिसंबर में 2.2 फीसदी रह गई। यह पिछले 18 महीनों की सबसे न्यूनतम दर है। यहां तक कि खाद्य और ईंधन वस्तुओं को निकाल दिया जाए तो शेष खुदरा महंगाई भी अक्टूबर के 6.2 फीसदी से कम होकर दिसंबर में 5.6 फीसदी रह गई। इससे भी अहम बात यह है कि मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान भी कमजोर पड़ा है। आरबीआई के सर्वेक्षण के मुताबिक दिसंबर 2018 में आम परिवारों का मुद्रास्फीतिक अनुमान भी तीन महीने आगे के परिदृश्य से 80 आधार अंक कमजोर पड़ा। वहीं अगले 12 महीने के परिदृश्य में यह 130 आधार अंक कम हुआ। इसी प्रकार कच्चे माल की लागत के मामले में मुद्रास्फीति का उत्पादकों का आकलन तीसरी तिमाही में कम हुआ। यह जानकारी आरबीआई के औद्योगिक पूर्वानुमान सर्वेक्षण में विनिर्माण कंपनियों द्वारा दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अगर 2019 में मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद की जाए तो खुदरा महंगाई को 4 फीसदी (2 फीसदी ऊपर नीचे) रखने का लक्ष्य तय किया जाएगा। माना यही जा रहा है कि आगामी 12 महीनों के दौरान यह 2.8 फीसदी से 3.9 के दायरे में रहेगी।

आरबीआई के सीमित दायरे में रहने का लाभ यह हुआ कि आरबीआई को वृद्धि से जुड़े नीतिगत कदम उठाने का अवसर मिला है। हमारे देश में अभी भी वाणिज्यिक क्षेत्र का बैंक ऋण और वित्तीय प्रवाह व्यापक पैमाने पर नहीं है। इतना ही नहीं वैश्विक वृद्धि में आया ठहराव और व्यापारिक तनाव भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में भले ही आरबीआई आने वाले वर्ष के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं बदले लेकिन उसने यह रेखांकित किया है निजी निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने और निजी खपत में इजाफा करने की आवश्यकता है।

मौद्रिक नीति समीक्षा के अलावा आरबीआई गवर्नर ने ऐसे नियामकीय उपायों की भी घोषणा की जो वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाने और उनकी गहराई बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। खासतौर पर संकटग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उपाय घोषित किए गए। आरबीआई ने मूल निवेश कंपनियों के अलावा सभी एनबीएफसी को ऋण की आवक सुनिश्चित करने के लिए उन तक बैंकों का रेटिंग के आधार पर तय जोखिम सुनिश्चित करने की बात कही है। कह सकते हैं कि ताजातरीन मौद्रिक नीति वक्तव्य आरबीआई के मूल्य स्थिरता के लक्ष्य और सरकार की उच्च आर्थिक वृद्धि की चिंताओं के बीच एक किस्म की सुसंगतता का संकेत देता है। यह देखना सुखद है क्योंकि हालिया अतीत में दोनों संस्थानों के रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केवल राजकोषीय फिसलन ही एक आशंका है। परंतु इस दिशा में भी किसी पेशकदमी के पहले आरबीआई प्रमाण चाहता है।

बिनय सिन्हा

भारत में रोजगार की वास्तविक तस्वीर

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नतीजों की रोजगार और बेरोजगारी के पिछले सर्वेक्षणों से तुलना नहीं की जा सकती। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं **अमिताभ कांत**

एक अच्छे नीतिगत ढांचे के लिए उन मजबूत संस्थानों का सहयोग जरूरी होता है, जो नियमित रूप से अच्छे आंकड़े संग्रहीत और हस्तांतरित करते हैं। मेरा अच्छे आंकड़ों में पूरा भरोसा है। ये सही समस्या की पहचान करने के लिए जरूरी हैं ताकि उसके लिए उचित समाधान खोजे जा सकें। इस समय भारत में रोजगार के हालात को लेकर बहस चल रही है। इस संदर्भ में हमें अच्छे आंकड़ों की उपलब्धता सुधारने के लिए प्रयास करने की जरूरत है ताकि कहे-सुने पर आधारित बहस को वस्तुनिष्ठ सबूतों के जरिये खत्म किया जा सके। इस समय तीन परस्पर विरोधी मत हैं। पहला मत यह है कि आर्थिक वृद्धि बिना रोजगार में बढ़ोतरी के हो रही है, जिसका मतलब है कि भारत में रोजगार के अपर्याप्त मौके पैदा हो रहे हैं। दूसरा मत पहले के विपरीत है और यह कहता है कि रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। तीसरा मत पहले दोनों के बीच में है, जिससे मैं भी सहमत हूं। इसके मुताबिक पर्याप्त रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन वास्तविक चुनौती अच्छे भुगतान वाले गुणवत्तायुक्त रोजगार पैदा करना है।

दुर्भाग्य से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए प्रायोगिक दो वर्षीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के पहले साल के आंकड़े पूरी तरह सत्यापन से पहले ही लीक हो गए। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट अधूरे आंकड़ों के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंच गईं, जिनसे वर्तमान हालत में कोई मदद नहीं मिली बल्कि भ्रम और बढ़ा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) का सदस्य होने के नाते तथ्यों को जनता के सामने लाना मेरा विशेषाधिकार है। यह रिपोर्ट न तो मुझे उपलब्ध कराई गई और न ही मंजूरी के लिए भेजी गई। यह रिपोर्ट मुझे तब उपलब्ध कराई गई, जब मैंने आंकड़ों के लीक होने के विवाद के बाद इसकी मांग की। इस रिपोर्ट को मेरी मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 5 दिसंबर को हुई बैठक में केवल कार्यकारी चेयरमैन पी सी मोहनन ने हिस्सा लिया था। यहां तक कि जेवी मीनाक्षी भी बैठक में मौजूद नहीं थीं। यह सर्वेक्षण पहली बार हो रहा था, इसलिए एक तय मानदंड के हिसाब से आधिकारिक आंकड़े जारी करने की प्रक्रिया कड़ी जांच और पुष्टि से गुजरनी चाहिए। निश्चित रूप से इन आंकड़ों की समकक्ष विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए थी।

इस रिपोर्ट से यह धारणा बनी है कि पीएलएफएस सर्वेक्षण के नतीजे दर्शाते हैं कि भारत में बेरोजगारी पिछले रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) की तुलना में काफी बढ़ी है। पिछला ईयूएस 2011-12 में हुआ था। यह गलत है क्योंकि पिछले सर्वेक्षणों और नए पीएलएफएस की आसानी से तुलना नहीं की जा सकती। पीएलएफएस दो वर्षीय प्रायोगिक सर्वेक्षण है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी। इसमें एक तिमाही शहरी सर्वेक्षण और एक सालाना ग्रामीण सर्वेक्षण भी शामिल है। इसका मकसद जल्दी-जल्दी श्रम बाजार के आंकड़े जारी करना है। इसलिए यह पिछले ईयूएस सर्वेक्षण से अलग था। ईयूएस सर्वेक्षण पांच साल में एक बार होता था। पीएलएफएस में इस्तेमाल की जाने वाली नमूनों की तकनीकों को अद्यतन बनाया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना का इस्तेमाल कर एक अलग नमूने ढांचे का इस्तेमाल किया गया है और आंकड़े संग्रहीत करने की नई पद्धतियां अपनाई गई हैं।

मैं आपको बताता हूं कि कैसे रोजगार में कमी का 2011-12 के सर्वेक्षण की तुलना पर आधारित निष्कर्ष गलत है। रोजगार के आंकड़ों के अलावा यह सर्वेक्षण देश की कुल आबादी के अनुमान जैसे बुनियादी जनांकिक आंकड़े भी पेश करता है।

पीएलएफएस का अनुमान है कि 2017-18 में भारत की कुल आबादी 2011-12 के ईयूएस सर्वेक्षण से कम होगी। अगर हम इन सभी तुलनाओं को बिना सही-गलत का ध्यान दिए बिना स्वीकार करते हैं तो हमें यह शीर्षक देना चाहिए कि 'छह वर्षों में भारत की आबादी घटी।' अगर व्यक्ति इस बारे में विचार करता है कि दोनों सर्वेक्षणों की पद्धति और कवरेज समान थी और पिछले ईयूएस सर्वेक्षणों (2004-05, 2009-10 और 2011-12) के दौरान अनुमानित आबादी में देश की आधिकारिक जनसंख्या वृद्धि दर के समान बढ़ोतरी हुई है तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि छह वर्षों में आबादी के अनुमान घटेंगे।

एक अन्य अजीब रुझान शहरीकरण की दर है। इसे देखकर लगता है कि यह 2011-12 से 2017-18 के दौरान लगभग थम गई है। यह उन विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के अनुमानों से ठीक विपरीत है, जो यह संकेत देते हैं कि भारत में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। भारत के तेज शहरीकरण की पुष्टि नासा की रात्रि लाइटों की उपग्रह तस्वीरों से भी होती है। क्या हम अनुभवाश्रित साक्ष्यों के बावजूद यह मानेंगे कि भारत में शहरीकरण थम गया है।

वर्तमान बहस में बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि रोजगार सृजन कार्यबल की वृद्धि की तुलना में सुस्त है। हालांकि पीएलएफएस की 2011-12 के सर्वेक्षण से तुलना करने पर पता चलता है कि देश में नियोजित लोगों की कुल संख्या भी 2011-12 से हर साल 20 लाख कम हो रही है। यह अन्य उपलब्ध सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए इस अवधि में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक वृद्धि हर क्षेत्र- बुनियादी ढांचे से लेकर आवास, परिवहन से लेकर स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाओं से लेकर खुदरा तक के विस्तार की बदौलत आई है। यह समझ से बाहर है कि नियोजित कार्यबल की संख्या में कमी के साथ इतनी वृद्धि संभव है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में वृद्धि उत्पादकता और पूंजी संग्रह की बदौलत हो रही है।

ब्रोकरेजों की स्वतंत्र रिपोर्टों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या घटकर 5 करोड़ से कम रह गई है, जो वर्ष 2011 में 26.8 करोड़ थी। यह बताना मुश्किल होगा कि यदि बेरोजगारी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है तो कैसे गरीबी में इतनी तेजी से कमी आ सकती है। अंत में, बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी पीएलएफएस के अन्य नतीजों की विरोधाभासी नजर आती है। पीएलएफएस के अन्य नतीजों में सामने आया है कि विभिन्न रोजगारों में आमदनी और मेहनताना बढ़ रहा है। अगर श्रम बाजार के हालात इतने खराब हैं, जितने बेरोजगारी की दर बता रही है तो आर्थिक तर्क यही कहेगा कि मेहनताने में कमी या कम से कम स्थिरता जरूर आएगी। लेकिन मेहनताने में कोई कमी नहीं आई है। उदाहरण के लिए ग्रामीण महिलाओं की आमदनी या पारिश्रमिक जुलाई-सितंबर 2017 से लगातार हर तिमाही में बढ़ा है। इसमें पिछली तिमाही में क्रमशः 13 फीसदी और 8 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है। पीएलएफएस में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी की दर सबसे अधिक बताई गई है।

(इस आलेख का दूसरा और अंतिम भाग शनिवार को प्रकाशित होगा। लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

अच्छा कारोबारी माहौल बनाने में अब भी जूझ रहा भारत

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

जब आप भारतीय कंपनियों के उन लोगों की फेहरिस्त बनाते हैं, जो 2017 के उत्तरार्द्ध से लेकर 2018 के आखिर तक सुर्खियों में रहे तो यह सामने आएगा कि ज्यादातर उदाहरण कुप्रबंधन, उचित जांच-पड़ताल का अभाव, कारोबारी फैसलों और धोखाधड़ी के हैं। इनमें नीरव मोदी, विजय माल्या, नरेश गोयल, सुभाष चंद्रा, आईएलऐंडएफएस, चंदा कोछड़, रुइया परिवार, अनिल अंबानी, शिखा शर्मा, राणा कपूर आदि शामिल हैं।

सफलता हासिल करने वाले उद्यमियों में कुछ ही नाम शामिल हैं, जिनमें मुकेश अंबानी, ओयो के रितेश अग्रवाल और फ्लिपकार्ट के सचिन और बिन्नी बंसल (लेकिन केवल सफल बिक्री करने के लिए) आदि शामिल हैं।

इसलिए क्या भारतीय कारोबारी, प्रबंधक और बैंकर औसत दर्जे से नीचे के हैं? या वे उचित कारोबारी माहौल न होने से पीड़ित हैं, जिसमें लॉबिइंग नियमों पर भारी पड़ रही है और नीति-निर्माण में टिकाऊपन नहीं है? आप पाएंगे कि वजह दोनों हैं। विजय माल्या, नरेश गोयल और सुभाष चंद्रा ने स्वीकार किया है उन्होंने गलत फैसले लिए। पहले दोनों व्यक्तियों के लिए नाकाम होने का मुख्य कारण लागत को नियंत्रित नहीं कर पाना रहा है, जो दुनिया में किसी भी विमानन कंपनी के लिए सबसे जरूरी है। गोयल के मामले में यह कहना गलत होगा कि वह अब जिस स्थिति में हैं, उसकी वजह केवल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है। उनकी लागत एवं इससे संबंधित अन्य चुनौती- कर्मचारी प्रबंधन के साथ जद्दोजहद कम से कम एक दशक से चल रही है। उन्हें ये चुनौतियां 2006 में डूबती एयर सहारा को खरीदने के फैसले की विरासत में मिली हैं।

टीवी पर चले 2008 के उस नाटक को याद कीजिए। जब उन्होंने करीब 1,900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। फिर देर रात नाटकीय संवाददाता सम्मेलन के बाद बहाल किया गया। युवा प्रदर्शनकारी जेट एयरवेज की अपनी चमकीली पीली वर्दी और काले चश्मे पहनकर एकत्रित हुए। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में गोयल आए, जहां उन्होंने आंसू बहाए और अपनी दिवंगत मां की कसम खाते हुए कहा कि उनके दिल में कर्मचारियों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है।

माल्या ने भी एक अभिनेता की छवि बनाई, लेकिन उनके नाटक में किंगफिशर एयरलाइंस की आपात लैंडिंग अप्रत्याशित थी। माल्या ने भी अधिग्रहण का एक गलत फैसला लिया। उन्होंने विदेशी मार्गों पर उड़ानों के लिए सरकारी नियमों को मात देने के लिए एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया। उनका यह फैसला भी उसी तरह गलत साबित हुआ, जिस तरह इकनॉमी क्लास के यात्रियों को बिज़नेस क्लास की सुविधाएं मुहैया कराने की उनकी रणनीति। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी कारोबारी असफलता करार दिया था। मगर उनकी इस बात से बैंक सहमत नहीं हैं। बैंकों के 7,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं। माल्या जब ऋण लेने की कोशिश कर रहे थे तब यह सवाल उठा कि कैसे विमानन को 'बुनियादी ढांचे के ऋण' का रूप दिया गया।

वर्ष 2012 में यह विमानन कंपनी बंद हो गई, जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इसके बाद रिपोर्ट आईं कि ऋणदाता बहुत सी कारों, लक्जरी घरों और निजी जेट पर कब्जा कर रहे हैं। इससे भी बड़ी खबर यह आई कि अपना शराब का मुख्य कारोबार डियाजियो को बेचने के बाद वह ब्रिटेन भाग गए हैं। इसके बाद प्रत्यर्पण की सुनवाई शुरू हुई।

सुभाष चंद्रा के एस्सेल समूह के शेयरों में पिछले सप्ताह भारी गिरावट आई थी। चंद्रा ने खुलकर यह बताया कि वह इस हालत में क्यों पहुंचे। इन कारणों में बुनियादी ढांचे में 'गलत बोलियां,' डी2एच के अधिग्रहण में एक अहम गलती, पारिवारिक कारोबार को बांटने के दौरान भारी कर्ज लेना और आईएलऐंडएफएस संकट आदि शामिल हैं। आईएलऐंडएफएस संकट के बाद उनकी कर्ज लौटाने की क्षमता कम हो गई। उनके मुख्य मीडिया कारोबार के अलावा विविधीकरण भी ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी समस्याओं का आरोप 'विरोधी ताकतों' पर लगाया, जिन्होंने उनकी कंपनी के शेयर जानबूझकर गिराए हैं।

लागत को नियंत्रित रखना और बुद्धिमता से विविधीकरण करना प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत हैं। आईएलऐंडएफएस समेत बहुत से समूह इसलिए नाकाम हुए हैं क्योंकि उन्होंने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महंगी परियोजनाओं पर भारी खर्च कर दिया। यह क्षेत्र अप्रत्याशित सरकारी नीति के जाल में इतना जकड़ा हुआ है कि अब भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ज्यादातर फंसे हुए कर्ज इसी क्षेत्र में हैं।

लेकिन बुनियादी प्रबंधन के लिए उचित जांच-पड़ताल भी जरूरी है। ऐक्सिस बैंक की शिखा शर्मा और येस बैंक के राणा कपूर एक समय भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मुख्य चेहरे थे। दोनों को केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इन्हीं आधारों पर अपना पद छोड़ने को कह दिया। चंदा कोछड़ के खिलाफ जांच के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उनके मामले से यह तो पता चलता है कि उन्होंने हितों के टकराव के मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया।

सफल उद्यमियों में अग्रवाल के ओयो रूम्स की लगातार और भारी वृद्धि साफ तौर पर एक कारोबारी सफलता है। अब यह कमरों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। यह विदेश में भी पांव पसार रही है। मुकेश अंबानी की जियो आज भारत के दूरसंचार क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकत है। यह दूसरे पायदान पर केवल इसलिए पहुंच पाई है क्योंकि उसने भारत के प्रतिस्पर्धा और नियामकीय कानूनों की कमजोरियों का फायदा उठाया है। क्या वह नियम आधारित अन्य किसी देश में इतना दबदबा कायम करने में सफल होती?

कुल मिलाकर तस्वीर धुंधली है। आर्थिक उदारीकरण को शुरू हुए करीब तीन दशक बीत चुके हैं। इसके बावजूद भारत एक अच्छा कारोबारी माहौल पैदा करने में जूझ रहा है। यह कारोबारियों के लिए उस कानूनी और नियामकीय माहौल के बारे में काफी कुछ बयां करता है, जिसमें वे काम कर रहे हैं।

कानाफूसी

दावा या हकीकत!

भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (इनेलो) नेता अभय सिंह चौटाला ने उन रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया जिनमें कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के साथ उनका गठबंधन दबाव के दौर से गुजर रहा है। जींद उपचुनाव के नतीजों के बाद ऐसी अटकलें जोर पकड़ रही थीं। अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों दल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। अभय, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं। जींद उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला दूसरे स्थान पर रहे जबकि इनेलो प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। अभय के भाई अजय सिंह चौटाला, जो फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं, वह जेजेपी के संरक्षक हैं और उनके दो बेटे दिग्विजय और दुष्यंत उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि उनकी पार्टी तब तक इनेलो से इस विषय में कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक कि चौटाला परिवार आपसी लड़ाई खत्मकर एकजुट नहीं होता।

आपका पक्ष

पीएम किसान योजना के पेच

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को 6,000 रुपये सालाना आय समर्थन की घोषणा की है। इस योजना का नाम पीएम किसान योजना रखा गया है। अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना की घोषणा से किसानों की स्थिति में सुधार संभव है। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार गठन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। इस पांच वर्षों में कितने किसानों की आय बढ़ी है इसका कोई आंकड़ा शायद ही हो। अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना की घोषणा करना किसानों की आय दोगुनी करने की योजना की विफलता को दर्शाता है। अंतरिम बजट में किसानों को आय समर्थन की घोषणा तो की गई लेकिन इसके पेच अब सामने निकल कर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भेजे गए दिशानिर्देश में यह तथ्य सामने आए हैं। दिशानिर्देश में मापदंड तय किए गए हैं जिसके तहत सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर किसान परिवार के सदस्य स्थानीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी करते हैं तो उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट हैं तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर किसान परिवार में भूतपूर्व सांसद, विधायक या जिला पंचायत के चेयरमैन हैं तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अगर किसी किसान परिवार के सदस्य इन पदों पर हों लेकिन वे परिवार से अलग रह रहे हों तो ऐसी स्थिति में क्या वह परिवार योजना से वंचित हो जाएगा। सरकार को एकल परिवार देखना चाहिए तथा उस परिवार का वंश नहीं देखा जाना चाहिए। इससे जरूरतमंद किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए पीएम किसान योजना की घोषणा की है

किशोर कुमार, नोएडा

रोजगार देने वालों को मिले प्रोत्साहन

सरकार श्रम कानूनों को सरल व लचीला बनाना चाहती है। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का दबाव है कि घटते रोजगार की स्थिति में श्रम कानूनों को सरल बनाना और घातक होगा। सख्त श्रम कानून से बचने के लिए उद्योग द्वारा ऑटोमैटिक मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। पूंजी सघन (जिसमें श्रम के मुकाबले ज्यादा पूंजी लगे) उत्पादन पर सख्त श्रम कानून से रोजगार उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। श्रम सघन उत्पादन को प्रोत्साहित करने से ही समस्या का निदान होगा। इसलिए जरूरी है कि जो उद्यमी रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनें। इस नीति से देश में श्रम सघन उत्पादन की लागत बढ़ेगी, जबकि प्रतिद्वंद्वी देशों में पूंजी सघन उत्पादन से लागत कम रहेगी। इस वास्तविक समस्या का निदान दूसरे देशों के पूंजी सघन उत्पादन पर आयात कर बढ़ाकर अपने श्रम सघन उत्पादन पर निर्यात सब्सिडी देनी होगी। जिससे हमारा श्रम सघन उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगा।

वीरेंद्र शर्मा, चंडीगढ़

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।